



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ४२
पटना, बुधवार, २५ आश्विन १९४० (श०)
१७ अक्टूबर २०१८ (ई०)

विषय-सूची		पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	---	
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4—बिहार अधिनियम	---	
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9—विज्ञापन	---	
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---	
पूरक	---	
पूरक-क	---	

2-3

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 1/एम02-60-05/2018 गृ0आ0-8883

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

संकल्प

10 अक्टूबर 2018

श्री विवेक कुमार, भा0पु0से0 (2007), तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध विशेष निगरानी ईकाई, बिहार, पटना द्वारा संज्ञेय अपराध के लिए धारा 13(2) सह पठित 13(1)(e) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत केस दर्ज करने एवं मामला अनुसंधानान्तर्गत होने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3 (3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय संकल्प सं0 3290, दिनांक 17.04.2018 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के अनुलग्नक II में विहित प्रक्रिया के आलोक में श्री कुमार के निलंबन के संबंध में अपेक्षित प्रतिवेदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजते हुए निलंबन की सम्पुष्टि हेतु अनुरोध किया। साथ ही, मामला अभी भी अनुसंधानान्तर्गत होने एवं श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संभावना को दृष्टिपथ में रखते हुए श्री कुमार को 30 दिनों के बाद की अवधि में भी उन्हें निलंबित रखने हेतु निलंबन की सम्पुष्टि हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया। इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त नियमावली के नियम 3 (3), जिसके अंतर्गत श्री कुमार को निलंबित किया गया है, के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि उक्त नियम के अनुसार श्री कुमार के निलंबन की सम्पुष्टि भारत सरकार से आवश्यक नहीं है।

3. अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(8)(a) के अद्यतन प्रावधान के अनुसार निलम्बन, विस्तारण के पूर्व 60 दिनों तक वैध रहता है और इसका विस्तारण पहली बार अधिकतम 120 दिनों के लिए किया जा सकता है। भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र के आलोक में श्री विवेक कुमार, भा0पु0से0 (2007) के निलंबन की अवधि 60 (साठ) दिनों तक अर्थात् दिनांक 17.04.2018 से 15.06.2018 तक वैध थी। श्री कुमार के निलंबन अवधि को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(8)(a) के आलोक में दिनांक 15.06.2018 के आगे 120

दिनों तक अर्थात् दिनांक 13.10.2018 तक विस्तारित करने की अनुशंसा निलंबन समीक्षा समिति द्वारा की गयी। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प सं० 5138, दिनांक 12.06.2018 द्वारा श्री कुमार की निलंबन अवधि को दिनांक 15.06.2018 के आगे 120 दिनों तक अर्थात् दिनांक 13.10.2018 तक विस्तारित किया गया।

4. विशेष निगरानी ईकाई, बिहार, पटना द्वारा अपेक्षित कथन प्रपत्र I से VI उपलब्ध कराते हुए में सूचना हेतु श्री विवेक कुमार से अनुरोध किया गया। बार-बार अनुरोध किये जाने के बाद भी वांछित सूचना श्री कुमार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है अर्थात् श्री विवेक कुमार द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है।

5. विशेष निगरानी ईकाई द्वारा पत्रांक 221 दिनांक 09.07.2018 के माध्यम से कांड से संबंधित तलाशी/जप्ति सूचियों की प्रति एवं स्थल पर उपलब्ध सामग्रियों के Inventory list की प्रतियाँ उपलब्ध करायी गयी है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त थाना कांड अभी भी अनुसंधानान्तर्गत है और जांच पूरी होने में अभी समय लगने की संभावना है। ऐसी स्थिति में श्री कुमार के निलंबन अवधि के विस्तारण के संबंध में दिनांक 04.10.2018 को निलंबन समीक्षा समिति द्वारा विचार किया गया तथा विचारोपरांत समिति द्वारा श्री कुमार के निलंबन की अवधि दिनांक 13.10.2018 के आगे 180 दिनों तक अर्थात् दिनांक 11.04.2019 तक विस्तारण करने की अनुशंसा की गयी, जिसे अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

6. अतः अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के संशोधित प्रावधानों के अनुरूप निलम्बन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री विवेक कुमार, भा०पु०से० (2007), के निलम्बन अवधि को दिनांक 13.10.2018 के आगे 180 दिनों अर्थात् दिनांक 11.04.2019 तक विस्तारित की जाती है।

7. श्री विवेक कुमार, भा०पु०से० (2007) को निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 30—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>